दहशत

जी इन्फ्रा कंपनी पर लापरवाही के आरोप, राजनीतिक संरक्षण की चर्चा, ग्रामीणों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

ब्लास्टिंग से दहशत में बैगा टोला ढोढ़ा, मकानों में आ रहीं दरारें

डिंडोरी, नवभारत 13 मई। शहपुरा तहसील अंतर्गत ग्राम बैगा टोला ढोढ़ा में इंटेकवेल निर्माण कार्य के दौरान हो रही भारी ब्लास्टिंग अब ग्रामीणों के लिए भय और परेशानी का कारण बन गई है। लगातार किए जा रहे विस्फोटों से गांव के कई मकानों की दीवारों, छतों और फर्श में दरारें पड़ने लगी हैं।

ग्रामीणों ने तहसीलदार शहपुरा को आवेदन सौंपकर जी इन्फ्रा कंपनी पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण स्थल पर प्रतिदिन हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे पूरा गांव दहल उठता है। विस्फोटों से उत्पन्न कंपन के कारण मकानों को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है।

ब्लास्टिंग से पहले नहीं दी गई सूचना

आरोप है कि ब्लास्टिंग से पहले ग्रामवासियों को किसी प्रकार की सूचना तक नहीं दी जाती, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित मकानों की जांच कराकर क्षतिपूर्ति दिलाने तथा संबंधित कंपनी और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में पंचनामा तैयार कर तहसीलदार कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

भाजपा के नेता का नाम आ रहा सामने

मामले में भाजपा के एक प्रभावशाली नेता का नाम भी चर्चाओं में सामने आ रहा है। सूत्रों की मानें तो पूर्व में अवैध ब्लास्टिंग के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हो, इसके लिए संबंधित प्रभावशाली नेता ने विशेष दिलचस्पी दिखाई थी। हालांकि तब तक मामला इतना तूल पकड़ चुका था और पुलिस को भी विवश होकर प्रकरण दर्ज करना पड़ा। क्षेत्र में यह चर्चा भी जोरों पर है कि इसी राजनीतिक संरक्षण के चलते जल निगम और ठेकेदार के हौसले बुलंद हैं।

जनपद अध्यक्ष ने किया निरीक्षण

ग्रामीणों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद जनपद अध्यक्ष शहपुरा प्रियंका आमों ने मंगलवार को निर्माण स्थल और प्रभावित मकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौके से ही एसडीएम शहपुरा से चर्चा कर ग्रामीणों की समस्याओं और सुरक्षा संबंधी चिंताओं से अवगत कराया।

आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन और चक्का जाम को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। गौरतलब है कि जिम्मेदार एजेंसियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से अब लोगों का आक्रोश खुलकर सामने आने लगा है।

इनका कहना है

जहां तक मेरी जानकारी में है कि शुक्रवार के दिन कंपनी को ब्लास्टिंग की अनुमति दी गई थी। मौके पर मैने टीम को चेक करने भी भेजा था कि हैवी ब्लास्टिंग हो रही है या कंट्रोल ब्लास्टिंग है। टीम द्वारा तो यही बताया गया कि कंट्रोल ब्लास्टिंग है और सेफ एंड टाउन पैरामीटर है। कुछ विशेष लोगों द्वारा शिकायत की जा रही है, जिसको गंभीरता से लिया जा रहा है। मैं तहसीलदार को भेज कर एक बार चेक करवा लेता हूं।

ऐश्वर्य वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, शहपुरा

विद्युत विभाग की लापरवाही से ग्रामीण हो रहे परेशान

मानिकपुर फीडर में महीनों से लो-वोल्टेज की समस्या, भीषण गर्मी में लोगों का हाल बेहाल

शहपुरा नवभारत 13 मई। शहपुरा विद्युत विभाग की लापरवाही का खामियाजा इन दिनों मानिकपुर फीडर से जुड़े ग्रामीण भुगत रहे हैं। टिकरिया, पड़रिया, रयपुरा सहित कई गांवों में पिछले कई महीनों से लगातार कम वोल्टेज की समस्या बनी हुई है, लेकिन शिकायतों के बाद भी विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।

भीषण गर्मी के दौर में ग्रामीणों के घरों में लगे कूलर और पंखे केवल नाम मात्र के चल रहे हैं। कई घरों में बल्ब तक ठीक से नहीं जल पा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि बिजली का वोल्टेज इतना कम रहता है कि घरेलू उपकरण लोड नहीं उठा पा रहे हैं, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है।

खराब बिजली व्यवस्था से लोगों में भारी आक्रोश

ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शहपुरा विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन देकर मामला टाल दिया गया। लगातार खराब बिजली व्यवस्था से लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शाम होते ही स्थिति और गंभीर हो जाती है। कम वोल्टेज के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, वहीं बुजुर्ग और महिलाएं गर्मी से परेशान हैं।

समय पर मेंटेनेंस और तकनीकी सुधार नहीं हो रहा

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभाग समय पर मेंटेनेंस और तकनीकी सुधार नहीं कर रहा है। यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण आंदोलन और प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। लोगों ने मांग की है कि मानिकपुर फीडर की तत्काल जांच कर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि एवं लाइन सुधार कार्य कराया जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके।

कचरा पृथकीकरण और जनभागीदारी पर दिया जोर

- शहपुरा में स्वच्छता चौपाल आयोजित

शहपुरा नवभारत 13 मई। स्वच्छ भारत मिशन एवं स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नगर परिषद शहपुरा द्वारा नगर को स्वच्छ, सुंदर और कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य से 'स्वच्छता चौपाल कार्यक्रम' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्ध नागरिकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लेकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। चौपाल में नागरिकों को गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने तथा निर्धारित डस्टबिनों का सही उपयोग करने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए बैनरों के माध्यम से चार रंगों के डस्टबिन की उपयोगिता समझाई गई।

लोगों ने सफाई व्यवस्था को लेकर सुझाव दिए-अधिकारियों ने नागरिकों से कहा कि वे घरों से निकलने वाले कचरे को पृथक कर नगर परिषद की कचरा गाड़ी में ही डालें। चौपाल में लोगों ने सफाई व्यवस्था को लेकर सुझाव भी दिए और नगर को स्वच्छ बनाए रखने की सामूहिक शपथ ली। कार्यक्रम का उद्देश्य शहपुरा को आदर्श एवं कचरा मुक्त नगर के रूप में विकसित करना है।

आयुष्मान प्रोत्साहन राशि वितरण में अनियमितता की होगी जांच

शहपुरा अस्पताल का मामला, विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा, कलेक्टर ने जिला स्तरीय समिति गठित की

शहपुरा, डिंडौरी, नवभारत 13 मई। विकासखंड शहपुरा के खंड स्तरीय चिकित्सालय में आयुष्मान भारत निरामय योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण में अनियमितता संबंधी शिकायत को कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए जांच कराई।

जांच में कई बिंदुओं पर लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितताओं के संकेत मिलने से कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय समिति गठित की गई। समिति में अनुविभागीय शहपुरा, पेंशन अधिकारी, जिला आयुषमान नोडल अधिकारी, जिला आयुषमान समन्वयक द्वारा जांच की गई। जांच के आधार पर डॉ. के विरूद्ध कार्यवाही हेतु कलेक्टर द्वारा उच्च अधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया है।

ड्यूटी रोस्टर में नाम नहीं होने के बावजूद राशि ली

जांच में पाया गया कि तत्कालीन मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी शहपुरा एवं वर्तमान में मेंहदवानी में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ. सत्येन्द्र परस्ते प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत होने के बावजूद चिकित्सक के रूप में अन्य डॉक्टरों की तुलना में कई गुना अधिक आयुष्मान प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर रहे थे। जांच प्रतिवेदन के अनुसार ड्यूटी रोस्टर में नाम नहीं होने के बावजूद उन्होंने मेडिकल स्पेशलिस्ट के रूप में राशि प्राप्त की।

डॉ. परस्ते ने हासिल की 7 लाख से अधिक की राशि

संयुक्त जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि डॉ. परस्ते द्वारा मेडिकल स्पेशलिस्ट के रूप में 30 प्रतिशत की दर से 7 लाख 1 हजार 992 रुपये 20 पैसे की राशि प्राप्त की गई, जबकि नियमानुसार उन्हें 10 प्रतिशत की दर से 2 लाख 33 हजार 997 रुपये 40 पैसे प्राप्त होना था। इस पर डॉ. परस्ते ने अपने जवाब में कहा कि वे मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे, इसलिए उन्हें 30 प्रतिशत की दर से राशि प्राप्त होना उचित है।

मातृत्व अवकाश पर रहने के बावजूद दी गई राशि

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कुछ कर्मचारियों को एक वर्ष से अधिक मातृत्व अवकाश पर रहने के बावजूद उस अवधि की प्रोत्साहन राशि आवंटित की गई। वहीं, वार्डबॉय के रूप में कार्य नहीं करने वाले कर्मचारी आशुतोष रजक के खाते में भी प्रोत्साहन राशि डाली गई। कुछ कर्मचारियों के स्थानांतरण के बाद भी उन्हें राशि आवंटित किए जाने की जानकारी जांच में सामने आई।

रिपोर्ट में कई बिंदुओं पर विरोधाभास पाया गया

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिमत में कहा गया कि जांच दल द्वारा दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किए बिना प्राथमिक आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। वहीं डॉ. परस्ते द्वारा दिए गए प्रतिउत्तर एवं जांच दल की रिपोर्ट में कई बिंदुओं पर विरोधाभास पाया गया। इसके चलते डॉ. सत्येन्द्र परस्ते के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित किए जाने की अनुशंसा की गई है। विभागीय जांच के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

एआई एप के माध्यम से होगी टीबी की स्क्रीनिंग

एआई तकनीक आधारित 'केट' एप का प्रशिक्षण आयोजित

डिंडौरी, नवभारत 13 मई। भारत सरकार की मंशा के अनुरूप टीबी रोगियों की शीघ्र पहचान एवं टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से जिले में आधुनिक एआई तकनीक आधारित 'केट' एप का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 मई को आयोजित हुआ, जिसमें डॉ. प्रज्ञा दुबे एवं उनकी टीम द्वारा जिले के समस्त सीएचओ को एप के उपयोग की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बताया गया कि 'केट' एप के माध्यम से केवल खांसी की आवाज के आधार पर यह पता लगाया जा सकेगा कि व्यक्ति की खांसी सामान्य है अथवा संक्रमणजनित। एप द्वारा संभावित टीबी रोगियों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग कर उन्हें तत्काल जांच के लिए चिन्हित किया जाएगा, जिससे समय पर उपचार शुरू किया जा सकेगा।

खांसी के विश्लेषण से संक्रमण की पहचान संभव

विशेषज्ञों के अनुसार एआई आधारित यह टूल टीबी रोग की स्क्रीनिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दो से तीन दिन की खांसी के विश्लेषण से ही संभावित संक्रमण की पहचान संभव हो सकेगी। प्रशिक्षण के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एप के संचालन एवं उपयोग की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। स्वास्थ्य विभाग ने आशा व्यक्त की है कि इस तकनीक के माध्यम से टीबी रोगियों की शीघ्र पहचान कर उपचार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

अवैध देशी और विदेशी शराब की गई जब्त, आबकारी विभाग की कार्यवाही में 3 प्रकरण दर्ज

डिंडौरी, नवभारत 13 मई। 11 एवं 12 मई को आबकारी विभाग वृत्त डिंडौरी द्वारा अवैध शराब रखने एवं बिक्री संबंधी प्राप्त शिकायतों के आधार पर दबिश देकर कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान भजन सिंह पारासर निवासी वार्ड क्रमांक 15 डिंडोरी के पास से एक थैले में 16 पाव रॉयल सिलेक्ट व्हिस्की विदेशी मदिरा बरामद की गई। वहीं फग्गन सिंह राठौर के कब्जे से 18 पाव देसी मदिरा जब्त की गई। इसी प्रकार विशाल भट्ट से 20 पाव गोवा रम, 14 पाव रॉयल सिलेक्ट व्हिस्की विदेशी मदिरा एवं 10 पाव देसी प्लेन मदिरा बरामद की गई।

50 पाव विदेशी व 28 पाव देसी प्लेन मदिरा बरामद की-कार्यवाही में कुल 50 पाव विदेशी मदिरा एवं 28 पाव देसी प्लेन मदिरा जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 8 हजार 600 रुपये बताई गई है। उक्त सभी प्रकरणों में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं।

गेहूं उपार्जन केंद्र कोटरी में किसानों को मिल रही राहत

चिल्हारी। उमरिया जिले के सेवा सहकारी समिति मर्यादित केंद्र कोटरी में इन दिनों शासन की समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी प्रक्रिया सुव्यवस्थित तरीके से संचालित की जा रही है। खरीदी केंद्र पर किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे क्षेत्र के किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच केंद्र पर छाया, पेयजल, बैठने और तौल व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने से किसानों को राहत मिल रही है। खरीदी केंद्र में प्रतिदिन बड़ी संख्या में किसान अपना गेहूं बेचने पहुंच रहे हैं। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए केंद्र परिसर में टेंट लगाकर छायादार व्यवस्था की गई है, जिससे तेज गर्मी के बीच किसानों को राहत मिल रही है।किसानों ने बताया कि इस बार खरीदी केंद्र में व्यवस्थाएं पहले की अपेक्षा काफी बेहतर हैं और उन्हें लंबे समय तक धूप में खड़ा नहीं रहना पड़ रहा है। केंद्र में गेहूं तौलने के लिए पर्याप्त तौल कांटे उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं, छापा, रंग और बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है ताकि खरीदी प्रक्रिया बिना किसी बाधा के सुचारु रूप से चलती रहे।

उमरिया जिला को किया जल अभाव ग्रस्त घोषित

- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

नवभारत उमरिया 13 मई। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राखी सहाय ने बताया कि जिले की सामान्य औसत वर्षा 1215.70 मिमी है। वर्ष 2024-25 में 1036.5 मि.मी. वर्षा हुई थी, जबकि वर्ष 2025-26 में 1373.6 मिमी वर्षा हुई है, जो सामान्य औसत वर्षा से अधिक है, किन्तु विगत वर्ष में अल्प वर्षा थी।

इस वर्ष सामान्य औसत वर्षा से 157.90 मिमी अधिक होने पर भी पेयजल स्त्रोतों का जल स्तर ग्रीष्म ऋतु में गिरना प्रारंभ हो गया है। इससे ग्रीष्म ऋतु तक पेयजल संकट के विकराल संभावना से इंकार नही किया जा सकता है।

सिंचाई के लिए भी पानी मिलना मुश्किल

भविष्य में पेयजल संकट की संभावित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी उमरिया ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जिले में नवीन निजी हैण्डपम्प, नलकूप खनन तथा सतही स्त्रोतों जैसे स्टॉप डैम, चेक डैम, नदी, तालाब आदि के पानी को सिंचाई प्रयोजन के लिए प्रतिबंधित करना आवश्यक हो गया है, ताकि जल स्तर नीचे जाने से जिले में पेयजल की स्थिति प्रभावित नहीं हो।

ट्यूबवेल उत्खनन पर रोक

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राखी सहाय ने मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सम्पूर्ण उमरिया जिले को जल अभाव ग्रस्त घोषित किया है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत आदेशित किया है कि सम्पूर्ण उमरिया जिले में नवीन निजी हैण्डपम्प, ट्यूबवेल उत्खनन कार्य तथा स्टाप डैम, चेकडैम, नदी, तालाब आदि के पानी को सिंचाई प्रयोजन के लिए आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा, तथा आदेश के उल्लंघन पर प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

बंदरबांट

करकेली में विकास की प्यास, योजना के नाम पर अधिकारी करोड़ों डकार गए, जमीन पर केवल धूल और सूखा

नल-जल योजना में भ्रष्टाचार, पानी के लिए तरस रहे ग्रामीण

करोड़ों स्वाहा, फिर भी गला सूखा

हैरानी की बात यह है कि करकेली में नल-जल और जल जीवन मिशन की बारी आई तो योजना धड़ाम हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदारों ने घटिया सामग्री का के नाम पर अब तक करोड़ों रुपये बहाए जा चुके हैं। पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सडकों को छलनी कर दिया गया, ऊंची-ऊंची टंकियां खड़ी कर दी गईं, लेकिन जब पानी देने उपयोग किया और अपनी जेबें भरकर रफूचक्कर हो गए। आलम यह है कि पाइपलाइन जगह-जगह से लीकेज है, हजारों लीटर पानी सडकों पर व्यर्थ बह रहा है, लेकिन किसी गरीब की प्यासी झोपड़ी तक एक बूंद नहीं पहुंच रहा।

नवभारत उमरिया 13 मई। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन जनपद मुख्यालय करकेली के जिम्मेदार अधिकारियों और रसूखदार ठेकेदारों ने इस कहावत को बदलकर जल ही भ्रष्टाचार का अवसर है कर दिया है।

गर्मी की तपिश शुरू होते ही जहां आम जनता का गला सूख रहा है, वहीं पीएचई विभाग के साहबों की तिजोरियां नल-जल योजना के ठंडे पानी से तर हो रही हैं। करकेली नगर क्षेत्र में नल-जल योजना अब जनसेवा का माध्यम नहीं, बल्कि सरकारी धन की बंदरबांट का एक शोपीस बनकर रह गई है।

ग्रामीणों का कहना है कि इस भीषण गर्मी और तपिश के बीच पीने के पानी की यहां विकराल समस्या बनी हुई है और आलम यह है कि लोगों को पेयजल की समस्या से रोज ही जूझना पड़ रहा है। यहां गांव में स्थित पानी की टंकी भी सिर्फ शो पीस बनकर रह गई है। जो हम ग्रामीणों को मुंह चिढ़ा रही है।

वेतन को तरसता ऑपरेटर, कमीशन में मस्त तंत्र

भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखिए कि योजना चलाने वाले ऑपरेटर पप्पू तिवारी को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। वह अपने परिवार और बीमार मां की परवरिश के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन संवेदनहीन तंत्र के पास उसे देने

साहबों की कुंभकर्णी नींद और कागजी घोड़े

जानकारों का कहना है कि पीएचई विभाग के उपयंत्री, एसडीओ और ईई साहब को सब मालूम है लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होना संदेह को जन्म दे रहा है जबकि अधिकारियों को पता है कि पिछले 5 महीनों से योजना बंद पड़ी है। लेकिन मजाल है कि साहेब अपनी एसी वाली कुर्सी छोड़कर जमीनी हकीकत देखने निकलें। आमजनों का आरोप है कि विभाग का काम केवल फर्जी बिल पास करने और कागजी घोड़े दौड़ाने तक सीमित रह गया है। जैसे ही बरसात आती है, अधिकारी चादर तानकर सो जाते हैं और गर्मी आते ही सुधार के नाम पर नए बजट का खेल शुरू हो हो जाता है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।